शोध मंथन Vol. XIII No.I Jan.-Mar.2022 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com*

सफाईकर्मी के संवेधानिक प्रावधानों की स्थिति का एक अध्ययन

प्राप्तिः 07.03.2022
स्वीकृतः 17.03.2022

डॉ० अनिल कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
एम०एस० कॉलेज, सहारनपुर
ईमेलः *kumar.anil@gmail.com*

सारांश

संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद आज भारतीय समाज में सफाईकर्मी हाशिए पर हैं, जो राज्य को उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करते हैं। उनके समुदाय अभी भी मुख्य रूप से देश की बुनियादी स्वच्छता सेवाओं को पूरा करने के लिए कार्यरत हैं। शिक्षा और रोजगार में सरकारी आरक्षण का लाभ उठाने के लिए आवश्यक साक्षरता कौशल की कमी के कारण, मैला ढोने वाले तेजी से बढ़ते शहरी वातावरण में रहने से जुड़ी नौकरी की गतिशीलता में भाग नहीं ले पाए हैं। जबकि इन आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को अन्य अनुसूचित जातियों द्वारा साझा किया जाता है, यह उनके स्वच्छता कार्य की 'अशुद्ध और प्रदूशणकारी प्रकृति' है जो मैला ढोने वालों को हाशिए पर रखती है। उनके रोजगार की प्रकृति अन्य अछूतों को भी उनके साथ भेदभाव करने का कारण बनती है। इन दबे–कुचले और दलित वर्गों की अमानवीय दुर्दशा से कुछ प्रमुख हस्तियां इतनी चिंतित हो गई हैं कि वे इन दुर्भाग्यपूर्ण लोगों की निराशाजनक स्थितियों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार हैं।

मुख्य बिन्दु

स्कैवेंजिंग, संवैधानिक प्रावधान, मानवतावादी, सामाजिक, आर्थिक आदि।

परिचय

जाति एक व्यावसायिक समूह है जो अनुष्ठान शुद्धता के मामले में है। पहले दो वर्णों के व्यवसायों को क्रमशः पुरोहित, प्रशासनिक और सैन्य कर्तव्यों के रूप में स्पष्ट रूप से कहा गया है। उनके नीचे वैश्य, आधुनिक उपयोग में, मुख्य रूप से व्यापारी थे, और अंत में शूद्र उत्पादक थे। सबसे नीचे अछूत हैं जिन्हें अशुद्ध, आधार और अशुद्ध माना जाता है, एक ऐसी स्थिति जो उनके सभी सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है। उन्हें मानव अपशिष्ट की सफाई, मूत्रालय (शौचालय की सफाई), मृत जानवरों का निपटान, सफाई और सफाई जैसे अशुद्ध और अपमानजनक कार्य करने होंगे। उन्हें जाति व्यवस्था के सदस्यों से अलग किया जाना चाहिए और गांवों के बाहरी इलाके में या अपनी बस्तियों में रहना चाहिए।

मैलाढोने वालों का अर्थ और परिभाषा

'मेहतर' एक ऐसा व्यक्ति है जो रात की मिट्टी, गंदगी, शवों को साफ करने, साफ करने, इकट्ठा करने, हटाने या अन्यथा संभालने के लिए लगा हुआ है या नियोजित है, कचरा, कचरा, आदि।

इस प्रकार, व्याख्या की गई, 'स्कैवेंजर' शब्द में सभी सफाई कर्मचारी शामिल होने चाहिए, भले ही वे आलीशान कॉर्पोरेट कार्यालयों में कार्यरत हों, जब तक कि वे कार्यात्मक रूप से इस समूह से संबंधित हों। वास्तव में, 'मेहतर' शब्द की परिभाषा ने समाज के वंचित वर्ग जैसे अनुसूचित जातियों और जनजातियों, अशुद्ध व्यवसायों में कार्यरत लोगों के कल्याण के बाद कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के नोडल मंत्रालय के बीच काफी कटुता पैदा कर दी है।

सफाई की उत्पत्ति

प्राचीन पुस्तकों में पारंपरिक व्यवसायों में मैला ढोने वाले या मिट्टी हटाने जैसी किसी जाति का उल्लेख नहीं है और न ही वे इस पेशे से विशेष रूप से हटाई गई किसी जाति का उल्लेख करती हैं। आज भी अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में मैला ढोने का व्यवसाय एक व्यवसाय के रूप में मौजूद नहीं है। एक पेशे के रूप में 'स्वीपिंग एंड स्कैवेंजिंग' का संस्थानीकरण हाल ही में हुआ प्रतीत होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक संदर्भ है कि मौर्य काल के दौरान शहरों में खुले स्थान में शौच करना प्रतिबंधित था, लेकिन मैला ढोने वालों द्वारा नाइट ऑयल के निपटान का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि पुराने ग्रंथ मैला ढोने की प्रणाली पर कुछ प्रकाश डालते हैं। डॉ. बिंदेश्वर पाठक (1991) ने अपने ''स्वतंत्रता के मार्ग'' में लिखा है कि 'शास्त्रों और अन्य साहित्य की सामग्री के अनुसार, मैला ढोना, विशेष रूप से मिट्टी का निपटान भारतीय समाज की एक विशेष जाति या जातियों द्वारा, सभ्यता की शुरुआत के बाद से शहरों के उद्भव के साथ अस्तित्व में रहा है।

मैनुअल स्कैवेंजिंग

भारत के अधिकांश हिस्सों में सूखे (गैर–फ्लश) शौचालयों (शौचालय) से मानव मल को मैन्युअल रूप से साफ करने और प्रस्तुत करने के लिए दैनिक कार्य का वर्णन करने के लिए 'मैनुअल स्कैवेंजिंग' शब्द का उपयोग किया जाता है। मैला ढोने का काम एक जाति–आधारित व्यवसाय है और हमेशा दलितों द्वारा किया जाता है। समाज में उनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हाशिए पर रहने की स्थिति गाँव के बसावट पैटर्न में उनके स्थान से परिलक्षित और प्रबल होती है। हालांकि, जाति में निम्न वे कार्यात्मक रूप से उच्च जातियों से संबंधित हैं। वे अपनी आजीविका के लिए उच्च जातियों के सदस्यों पर निर्भर हैं। मेहतर जाति की भागीदारी के बिना विवाह और मृत्यु की कुछ रस्में पूरी नहीं की जा सकतीं। उदाहरण के लिए, छत में सूर्य देवता की पूजा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पंखा और एक जाति हिंदू विवाह में विभिन्न अनुश्ठानों में उपयोग की जाने वाली टोकरी को सामाजिक रूप से उनकी रचना के रूप में स्वीकार किया जाता है।

आर्थिक स्थिति

मैला ढोने वाले आर्थिक रूप से शहर से विशेष रूप से पारंपरिक श्रमिकों के रूप में उच्च जातियों के सदस्यों से बंधे होते हैं। मैला ढोने वालों का पारंपरिक काम शहर में झाड़ू लगाना और कूड़ा हटाना है। इनमें से अधिकांश मैला ढोने वाले स्थायी या अस्थायी कर्मचारी के रूप में नगर निगम/निगम से जुड़े हैं। बाकी बड़े नर्सिंग होम, निजी कंपनियों या अन्य प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं जहां उनकी सेवाओं की आवश्यकता है। शहरी मैला ढोने वालों की स्थिति कुछ बेहतर है क्योंकि उन्हें महीने के अंत में वेतन मिल जाता है। इनके अलावा, ऐसे मैला ढोने वाले हैं जो व्यक्तिगत घरों की सेवा करके अपनी आजीविका कमाते हैं। यह वर्ग आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित है। ग्रामीण परिदृश्य अलग है।

ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों की सफाई के लिए गांव को विभिन्न सफाईकर्मी परिवारों में बांटा गया है। प्रत्येक ग्रामीण मेहतर परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी एक निश्चित संख्या में घरों (जजमानों) की सेवा करता रहा है। सिद्धांत रूप में, जजमानी प्रणाली श्रम विभाजन को व्यक्त करने के लिए वंशानुगत व्यक्तिगत संबंधों का उपयोग करती है। जजमान अपने मेहतर को समय–समय पर नकद, वस्तु के रूप में भुगतान के माध्यम से मुआवजा देता है। होली, दिवाली, छत और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों जैसे जन्म, उपनयन, मुंडन, विवाह और मृत्यु पर मैला ढोने वालों को कपड़े, भोजन, कच्चा माल आदि उपहार भी मिलते हैं।

बर्वे समिति

मैला ढोने और मैला ढोने वालों की स्थिति में सुधार की समस्या आजादी के बाद से लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित कर रही है। बॉम्बे की तत्कालीन सरकार ने 1949 में स्केवेंजर्स लिविंग कंडीशंस इंक्वायरी कमेटी के रूप में जानी जाने वाली एक समिति नियुक्त की, जिसमें स्वर्गीय श्री वी.एन. बरवे के अध्यक्ष के रूप में बॉम्बे राज्य में मैला ढोने वालों की रहने की स्थिति का अध्ययन और पूछताछ करने और तरीके और साधन सुझाने के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके काम की वर्तमान परिस्थितियों में सुधार करने और उनकी न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए। समिति ने 1952 में बॉम्बे सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1955 में गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को बहादुर समिति की प्रमुख सिफारिशों की एक प्रति परिचालित की, जिसमें उनसे इन सिफारिशों को अपनाने का अनुरोध किया गया क्योंकि वे वास्तव में व्यापक आवेदन करने में सक्षम थीं और सभी राज्य सरकारों द्वारा लाभप्रद रूप से लागू की जा सकती थीं।

मैला ढोने वालों को व्हील–बैरो और बेहतर उपकरणों की आपूर्ति के लिए योजना

भारत सरकार ने मैला ढोने के कार्य को मानवीय गरिमा के अनुरूप बनाने के लिए प्रथम कदम के रूप में नगर पालिकाओं आदि द्वारा नियोजित सफाईकर्मियों को मैला ढोने के काम के लिए व्हील–बैरो/हैंड कार्ट की आपूर्ति करने का सुझाव दिया ताकि रात की मिट्टी को सिर के भार के रूप में ले जाने की प्रथा हो। पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। जैसा कि यह महसूस किया गया था कि यदि नगर पालिकाओं आदि को अकेला छोड़ दिया जाए तो यह आवश्यकता पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के अभाव में पूरी नहीं हो सकती है, भारत सरकार ने 1957–58 में गृह मंत्रालय में 50% की सदस्यता की पेशकश की। राज्य सरकारों के माध्यम से ऐसी जरूरतमंद नगर पालिकाओं और अन्य स्थानीय निकायों को व्हील–बैरो/हैंड कार्ट की खरीद के लिए लागत, जो इस प्रकार के काम पर कार्यरत मैला ढोने वालों, व्हील–बैरो या हैंड कार्ट को समाप्त करने के लिए तुरंत प्रदान करने का उपक्रम कर सकते हैं। मिट्टी को हेड लोड के रूप में ले जाने के लिए और शेष 50% लागत को राज्य सरकारों की सहायता से या उसके बिना योगदान करने के लिए तैयार थे और सहायता अनुदान केवल ऐसे स्थानीय निकायों के लिए स्वीकार्य होगा जो इस प्रथा को पूरी तरह से रोकने के लिए सहमत हैं, न कि उन लोगों को योजना को टुकड़े–टुकड़े करना। लेकिन स्थानीय निकायों/राज्यों की प्रतिक्रिया बहुत खराब थी। कई मामलों में राज्य सरकारों को स्वीकृत राशि का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया था, और जिन मामलों में राशि का उपयोग किया गया था, वे नगण्य थे। मैला ढोने वालों को प्रदान किए गए व्हील–बैरो सबसे अनुचित और इतने भारी थे कि उन्हें मैला ढोने वालों द्वारा त्याग दिया जाना था।

पिछड़ा वर्ग आयोग (काका कालेलकर आयोग)

काका कालेलकर की अध्यक्षता में 1953 में नियुक्त प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने सफाईकर्मियों और सफाईकर्मियों की स्थिति को उप–मानव के

रूप में वर्णित किया। आयोग ने कहा कि ''हरिजनों के सतर्क समुदाय ने हमें उनकी स्थिति पर गौर करने के लिए मजबूर किया है, हालांकि तकनीकी रूप से समस्या हमारे संदर्भ की शर्तों के भीतर नहीं है। हमने हरिजन क्वार्टर का दौरा किया और उनकी स्थिति का अध्ययन किया। केवल ''उप–मानव'' शब्द ही उनकी स्थिति का उचित वर्णन कर सकता है। भंगी हमारे शौचालयों को साफ करते हैं और कुछ हद तक स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने में मदद करते हैं। भंगियों के बिना, पूरी आबादी को समीकरणों के कहर का सामना करना पड़ेगा। फिर भी, यही भंगी गंदगी भरे वातावरण में रहने को मजबूर हैं, और कुछ जगहों पर तो उन्हें अपने सिर पर मिट्टी ढोने के लिए भी कहा जाता है। मिट्टी के लिए पात्र रिसाव नहीं होना चाहिए। कोई भी समाज जो मानवता के एक वर्ग से इस तरह की अपमानजनक और अपमानजनक सेवा करने की अपेक्षा करता है, उसे खुद पर शर्म आनी चाहिए। इस संबंध में नगर पालिका सबसे बड़े पापी हैं। यह दलील कि उनके पास भंगियों के आवासों को सुधारने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, खोखली है। यदि शहर के पिताओं में इन दुर्भाग्यपूर्ण लोगों के लिए वही भावनाएँ होतीं जो वे अपने क्लर्कों और चपरासियों के लिए होती हैं, तो वे भंगियों को सभ्य घरों में रखने के लिए संसाधन खोजने में कामयाब होते। ब्रिटिश जेल के शौचालयों को साफ करने के लिए आश्रम के अपने एक ब्राह्मण सहयोगी को अनुमति प्राप्त करने के लिए महात्माजी को अनशन की धमकी देनी पड़ी थी। महात्मा गांधी को 'राष्ट्रपिता' कहना पसंद करने वाले सभी शहर के पिता हमारी सभ्यता से इस कलंक को दूर करने के लिए उनके तरीके से कुछ ठोस करें। भंगियों को अलग–अलग इलाकों में रहने की निंदा नहीं की जानी चाहिए। उन्हें वितरित किया जाना चाहिए और अन्य समूहों के बीच क्वार्टर दिए जाने चाहिए।''

हरिजन कल्याण के लिए केंद्रीय सलाहकार बोर्ड

गृह मंत्रालय ने गृह मंत्री स्वर्गीय पंडित गोबिंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में 1956 में हरिजन कल्याण के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया। इस बोर्ड ने अन्य बातों के साथ–साथ देश में सफाईकर्मियों और मैला ढोने वालों के काम करने और रहने की स्थिति की समीक्षा की और सरकार को इस उद्देश्य के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू करने की सिफारिश की।

मलकानी समिति

बोर्ड ने 12 अक्टूबर 1957 को हुई अपनी बैठक में एक समिति का गठन किया, जिसे मैला ढोने की स्थिति जांच समिति के रूप में जाना जाता है, जिसमें प्रो. एन.आर. मलकानी अध्यक्ष और सर्वश्री के.एल. बाल्मीकि, आर.के. बोस, एन.एस. काजरोलकर और पी.एन. राजाभोज को सदस्यों के रूप में बाल्टियों या टोकरियों में मैला ढोने वाले मैला ढोने वालों की अपमानजनक प्रथा को समाप्त करने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए कहा। समिति ने जनवरी 1958 में काम शुरू किया और दिसंबर 1960 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिओर्ट मैला ढोने वालों के लिए एक वास्तविक भावना से सूचित किया जाता है और इसमें न केवल मिट्टी को सिर पर भार के रूप में ले जाने की प्रथा को समाप्त करने के लिए, बल्कि गंदगी और गंदगी को हटाने के लिए भी ठोस सिफारिशें शामिल हैं।

प्रथागत अधिकारों पर समिति

केंद्रीय समाज कल्याण विभाग ने 1965 में प्रो. एन.आर. मलकानी, मैला ढोने वालों के प्रथागत अधिकारों के उन्मूलन के प्रश्न की जांच करने के लिए। समिति ने 1966 में सरकार को अपनी

रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने पाया कि जहां मैला ढोने का कार्य नगरपालिका द्वारा नहीं किया जाता है, वहां शौचालयों की निजी सफाई की जाती है और एक विशेष मैला ढोने वाले ने इस तरह के शौचालय को साफ करने के वंशानुगत अधिकार प्राप्त कर लिए हैं, जबकि दूसरे मैला ढोने वाले के खिलाफ एक समझ और समझौते से। किसी न किसी रूप में भुगतान प्राप्त करने वाले गृहस्वामी और मेहतर के साथ एक प्रथागत संबंध भी विकसित होता है।

पंड्या समिति

केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय श्रम आयोग ने श्री भानु प्रसाद पांड्या की अध्यक्षता में एक उप–समिति (1968–69) नियुक्त की, जो सफाईकर्मियों और मैला ढोने वालों के काम और सेवा की शर्तों को देखने के लिए थी। प्रथागत अधिकारों पर रिपोर्ट के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों के हाथ जो खुशी हुई। समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक यह थी कि ''केंद्र सरकार को उनके कामकाज, सेवा और रहने की स्थिति को विनियमित करने के लिए एक व्यापक कानून बनाना चाहिए जो पर्याप्त निरीक्षणालय और प्रवर्तन मशीनरी के लिए भी प्रदान करे''।

गांधी शताब्दी वर्ष

गांधी शताब्दी वर्ष (1969) के दौरान भारत सरकार ने सूखे शौचालयों को पानी से भरे फ्लश शौचालयों में बदलने के लिए एक विशष कार्यक्रम शुरू किया। इस योजना के तहत घरवालों को 25 फीसदी सब्सिडी और 75 फीसदी कर्ज आसान किश्तों में दिया जाता था. घरवालों को अपने सर्विस शौचालयों को पास के सार्वजनिक सीवर, यदि कोई हो, से जोड़ने की अनुमति दी गई थी।

हरिजन सेवक संघ

हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर, 1932 को पूना के पास यरवदा जेल में महात्मा गांधी के महाकाव्य–उपवास के परिणामस्वरूप हुई थी। यह उपवास ब्रिटिश सरकार के सांप्रदायिक पुरस्कार के विरोध में था जो तथाकथित अछूतों को हिंदू समाज से अलग करने की धमकी देता था। संघ का उद्देश्य सत्य और अहिंसक तरीकों से अस्पृश्यता का उन्मूलन करना, अछूतों की कठिनाइयों और अक्षमताओं को दूर करना और उन्हें अन्य हिंदुओं के साथ सभी क्षेत्रों में पूर्ण समानता का दर्जा दिलाना था।

सफाई विद्यालय, अहमदाबाद

सफाई विद्यालय, हरिजन सेवक संघ द्वारा श्री ईश्वर भाई पटेल के नेतृत्व में अहमदाबाद में एक स्वच्छता संस्थान स्थापित किया गया था और भंगी कश्त मुक्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सौंपा गया था, जो बेहतर उपकरणों के उपयोग के तरीके, दृष्टिकोण, उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्वच्छता निरीक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के अलावा कनिष्ठ और वरिष्ठ इंजीनियरों, राजमिस्त्री, सफाईकर्मियों और सफाईकर्मियों को शौचालय आदि की सफाई। नीति निर्माताओं और प्रशासकों को स्वच्छता के महत्व के बारे में समझाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अल्पकालिक पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

गांधी स्मारक निधि, पुणे

गांधी स्मारक निधि पुणे सेवा शौचालयों को फ्लश सेनेटरी शौचालयों में परिवर्तित करके और नए शौचालयों का निर्माण करके मैला ढोने के उन्मूलन के लिए काम कर रहा है, जिसमें मैला ढोने वालों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं होती है। निधि ने स्वच्छता शौचालयों के प्रसार और

निर्माण के लिए एक सेल भंगी मुक्ति योजना भी स्थापित की थी। निधि सामाजिक और नगरपालिका कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करती है जिसमें स्वच्छता शौचालय और बायो गैस संयंत्र के निर्माण के लिए प्रशिक्षण भी शामिल है।

सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन

भारत की सबसे गंभीर पर्यावरणीय स्वच्छता समस्याओं में से एक मानव अपशिष्ट का उचित प्रबंधन और निपटान है। इस बुनियादी स्वच्छता उपाय की उपेक्षा हमारे अधिकांश कस्बों और गांवों के विकास में एक पुरानी विशेषता है और अधिकांश जल जनित बीमारियों का कारण है। वर्तमान में 1991 की जनगणना द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में 76 प्रतिशत से अधिक लोगों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है और केवल 24 प्रतिशत लोगों के पास शौचालय की सुविधा है। इसलिए, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग उपलब्ध किसी भी खुले स्थान में शौच करते हैं। जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ, समस्या और विकट हो गई है और आम आदमी को सस्ती, सामाजिक रूप से स्वीकार्य और आसानी से उपलब्ध लागत पर शौचालय की सुविधा प्रदान करना आवश्यक है।

मैला ढोने वालों का पुनर्वास योजना

विभिन्न कम लागत वाले स्वच्छता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की उत्पत्ति का पता हमारे देश में, विशेष रूप से कस्बों और शहरों में, मैला ढोने वालों की समस्या की पहचान से लगाया जा सकता है। स्कैवेंजिंग मुख्य रूप से कुछ जातियों के लोगों का पेशा रहा है। ऐसी पहली समिति बर्वे समिति (1949–52), ''द स्कैवेंजर्स लिविंग कंडीशंस इंक्वायरी कमेटी'' थी। 1953 में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में नामित एक अन्य आयोग की स्थापना की गई थी। इसके बाद 1957 में 'द स्कैवेंजिंग कंडीशंस इंक्वायरी कमेटी' नामक एक अन्य समिति की नियुक्ति की गई थी, जिसकी अध्यक्षता में 1957 में स्थापना की गई थी। हरिजन कल्याण के लिए सलाहकार बोर्ड ने 1960 में प्रस्तुत किया। सफाईकर्मियों और मैला ढोने वालों की कार्य और सेवा शर्तों का अध्ययन करने के लिए एक अन्य समिति 1968 में स्थापित की गई थी (राष्ट्रीय श्रम आयोग)। लगभग सभी समितियों ने माना कि सबसे अच्छा समाधान बाल्टी के सूखे शौचालयों को कम लागत वाले शौचालयों में डाइजेस्टर (गड्ढों) से बदलना था। हालांकि, उस समय कोई कम लागत प्रणाली उपलब्ध नहीं थी और इसे निकट भविष्य में व्यावहारिक नहीं माना जाता था। इसलिए, यह सुझाव दिया गया था कि उपयुक्त उपकरणों का उपयोग करके शौचालयों की यांत्रिक सफाई और बेहतर आवास, उनकी जीवन शैली में सुधार के लिए स्वच्छता और स्वच्छता में प्रशिक्षण और इस प्रकार समाज में उनके अवशोषण में मदद करके मैला ढोने वालों की काम करने की स्थिति में सुधार किया जाए। 1969 में महात्मा गांधी शताब्दी वर्ष के दौरान, मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए गांधीजी की चिंता को उनकी पहली कार्य योजना को उजागर करके आवाज दी गई थी, जिसे 5 नवंबर, 1917 को गुजरात राज्य के एक छोटे से शहर घोरा में एक प्रार्थना सभा में सुझाया गया था। इस शहर में गांधीजी ने श्री की देखरेख में हरिजन समुदाय के उत्थान के लिए पहला आश्रम बनवाया। अप्पासाहेब पटवर्धन। महात्मा गांधी के इन विचारों पर जोर देकर इस बात पर जोर दिया गया कि रात की मिट्टी को आश्रम में रहने वाले सभी लोगों द्वारा निपटाया जाना चाहिए, न कि केवल मैला ढोने वालों द्वारा। उनकी भावनाओं को उनके अपने शब्दों के हवाले से सबसे अच्छी तरह

से व्यक्त किया गया है, ''मैं फिर से पैदा नहीं हो सकता, लेकिन अगर ऐसा होता है, तो मैं मेहतर के परिवार में फिर से जन्म लेना चाहूंगा ताकि मैं उन्हें अमानवीय, अस्वस्थ और घृणित रूप से ले जाने की प्रथा से मुक्त कर सकूं। रात की मिट्टी का एक हेडलोड''। इस प्रकार महात्मा गांधी द्वारा देश भर में सफाईकर्मियों की मुक्ति के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। कई सम्मेलनों और मैला ढोने वालों की समस्या के गहन अध्ययन के परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने बकेट शौचालयों को सीवर से जुड़ी वाटर फ्लश इकाइयों में परिवर्तित करने के लिए आसान किश्तों में चुकाने योग्य 25 प्रतिशत सब्सिडी और 75 प्रतिशत ऋण प्रदान किया। विभिन्न योजनाओं और कार्य योजनाओं में परिकल्पित बाल्टी या सूखी प्रिजियों को बदलने के लिए अतीत में किए गए प्रयास अधिक व्यवहार्य और किफायती नहीं थे। बकेट शौचालयों को पोर–फ्लश (पीएफ) इकाइयों में बदलने के लिए आंदोलन और गैर सरकारी संगठनों से बड़ी व्युत्पन्न प्रेरणा शक्ति। तमिलनाडु ने पचास के दशक के अंत में विकसित दो पिट पोर–फ्लश शौचालय प्रणाली को अपनाया। सुलभ इंटरनेशनल ने 1973 में इस कार्यक्रम को शुरू किया और पांच लाख से अधिक आबादी वाले पटना (बिहार) के भीड़भाड़ वाले इलाकों में 1977 तक लगभग 10,000 बाल्टी सूखे शौचालयों को पीएफ शौचालय इकाइयों में परिवर्तित कर दिया। इसने दिखाया था कि पारंपरिक बाल्टी या सूखे शौचालयों को बदलने के लिए शहरी क्षेत्रों में पीएफ शौचालय प्रणाली को उपयुक्त रूप से अपनाया जा सकता है।

समस्या का विधान

मैला ढोने वाले सामाजिक सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर हैं। रोजगार के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण पारंपरिक व्यवसायों के अनुरूप पाया गया था जो कि जाति समाज ने निर्धारित किया था। भारतीय व्यवस्था के तहत ये व्यवसाय वंशानुगत और कठोर प्रकृति के थे, ''आम तौर पर एक जाति व्यवस्था या संबद्ध जातियों का एक समूह कुछ कॉलिंग को अपने वंशानुगत व्यवसायों के रूप में मानता था, जिसे छोड़कर दूसरे की खोज में, हालांकि अधिक आकर्षक हो सकता है, यह सही नहीं माना जाता था''. पदानुक्रम में एक जाति जिस स्थान पर काबिज होती है, वह काफी हद तक उस व्यवसाय की प्रकृति से नियंत्रित होती है जिसका वह जाति समाज में अनुसरण करती है। ''मैला ढोने को एक अशुद्ध व्यवसाय माना जाता है और इस प्रकार उन्हें समाज के पारंपरिक व्यावसायिक ढांचे में निम्नतम स्थान दिया गया है। व्यवसायों को अशुद्ध माना जाता है क्योंकि वे आमतौर पर असहमति, अस्थिरता और अस्पृश्यता जैसे कलंक से जुड़े होते हैं। ''कस्टम ने उन्हें दास व्यवसाय अपनाने के लिए बाध्य किया जिसने उन्हें सामाजिक स्तर से नीचे रखा''।

भारत में मैला ढोने वाले सबसे कम हैं और अछूतों में अछूत हैं। भारतीय समाज के बहिष्कृत और अस्वीकृत होने के नाते, मैला ढोने वालों को सदियों से मानवीय अपमान सहना पड़ा है। उन्हें ''अशुद्ध'' माना गया है और इसके परिणामस्वरूप उन्हें अनुष्ठानिक रूप से टाला गया है। कई से अधिक लोगों द्वारा उन्हें मानव से कमतर बताकर त्याग दिया गया है। जबकि उनकी सेवाओं को अत्यधिक मूल्यवान के रूप में स्वीकार किया गया है, अक्सर समाज के अस्तित्व के लिए जरूरी है, इन दुखी लोगों को एक खतरनाक संक्रामक बीमारी की तरह माना जाता है, जो बहुत ही अपमानजनक दूरी और न्यूनतम सामाजिक संपर्क कहते हैं। उन्हें हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने और पूजा स्थलों में पूजा करने से रोक दिया गया है। अपने सामाजिक पतन के कारण, मैला ढोने वालों को सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के रूप में जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया है। जिन लोगों की वे सेवा करते हैं, उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए वे जो काम करते हैं, उसके महान महत्व

के बावजूद, उन्हें अपने भाग्य के हिस्से के रूप में अपने सामाजिक पतन, भेदभाव और वंचित स्थिति को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया है।

सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना से ही मैला ढोने वालों की समस्याओं के प्रति अपनी चिंता दिखाई है, जिसमें हाथ से मैला ढोने वालों के नियोजन को प्रतिबंधित किया गया था और इसके अभ्यास को संविधान द्वारा निशिद्ध किया गया था। लेकिन कानूनी उन्मूलन एक संस्थान में तुरंत नहीं मिटाया जा सकता है, जिसकी जड़ें अतीत में गहरी हैं और कुछ समुदायों के मनोविज्ञान में हैं। कार्य को पूर्ण करने के लिए अनुनय, उदाहरण एवं सामाजिक शिक्षा आवश्यक है। सामाजिक जीवन में व्यवहार का अभ्यास और राज्य और निजी एजेंसियों द्वारा आत्म विकास और आर्थिक जीवन और रहने की स्थिति की बेहतरी के लिए प्रदान किए गए अवसर उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए, वर्तमान अध्ययन सामाजिक–आर्थिक स्थितियों का विश्लेशण करने का एक प्रयास है। तमिलनाडु के मदुरै निगम में कार्यरत मैला ढोने वालों की संख्या।

निष्कर्ष

विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पुरुष और उत्पादक संपत्ति में कमाई करने वाले सदस्य महिला मैला ढोने वालों में प्रमुख कारक हैं जो उपभोग व्यय के स्तर को प्रभावित करते हैं। परिवार का आकार एक महत्वपूर्ण कारक है जो पुरुष और महिला मैला ढोने वालों में प्रति व्यक्ति आय, व्यय, बचत और ऋण के स्तर को निर्धारित करता है। संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद आज भारतीय समाज में सफाईकर्मी हाशिए पर हैं, जो राज्य को उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करते हैं। वे हाशिए पर हैं क्योंकि उनके समुदाय अभी भी मुख्य रूप से देश की बुनियादी स्वच्छता सेवाओं को पूरा करने के लिए कार्यरत हैं। हमारे दिमाग में जो नाम आता है, वह है बिहार के पटना के डॉ. बिंदेश्वर पाठक का। वह 'सुलभ स्वच्छता आंदोलन' के संस्थापक हैं। वह एक दार्शनिक की दृष्टि और एक मिशनरी के अमर उत्साह के साथ समकालीन भारत के एक महान मानवतावादी और समाज सुधारक हैं। उनके प्रयासों की बदौलत अछूतों को समाज में दूसरों के साथ घुलने–मिलने की अनुमति मिली है। वह लाखों मैला ढोने वालों के लिए मानव रोशनी और सम्मान की बहाली के लिए एक राष्ट्रीय धर्मयुद्ध के नेता हैं। उन्होंने सुलभ शौचालय प्रणाली के नाम से लोकप्रिय टू–पिट, पोर–फ्लश शौचालय की तकनीक विकसित की। उन्होंने मलिन बस्तियों में 7,500 से अधिक सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करवाया है। 10 मिलियन से अधिक लोग इन सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने सार्वजनिक शौचालयों से मानव मल के पूर्ण पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के लिए एक तकनीक भी विकसित की है।

सन्दर्भ

1. बर्मन, बी. के. रॉय. (एड.). (1961). सोशल मोबिलिटी अमंग द स्वीपर्स ऑफ इंडियाः सेंसस ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, गृह मंत्रालय।
2. बर्वे, वी. एन. (1958). स्कैवेंजर्स लिविंग कंडीशंस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्टः बॉम्बे स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ प्रिंटिंग स्टैटिस्टिकल, बॉम्बे स्टेट।
3. (1981). कंसोर्टियम ऑन रूरल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज ट्रस्टः रूरल सेनिटेशन टेक्नोलॉजी ऑप्शंस, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज ट्रस्ट, नई दिल्ली।

4. भास्करन, टी. आर. (1966). भारत में ग्रामीण शौचालयों पर किए गए कार्य की समीक्षा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, विशेष रिपोर्ट श्रृंखला संख्या 54, नई दिल्ली।
5. शर्मा, रमा. (1995). स्कैवेंजर इन इंडियन सोसाइटी, एम.डी. पब्लिकेशन्स प्रा। लिमिटेड, नई दिल्ली।
6. रतन, राम. (1960). ''दि चेंजिंग रिलिजन ऑफ द भंगिस ऑफ डेल्हीः ए केस ऑफ संस्कृ ताइजेशन'', विद्यार्थी (सं.), एस्पेक्ट्स ऑफ रिलिजन इन इंडियन सोसाइटी, रामनाथ केदारनाथ, मेरठ।
7. शर्मा, बी. डी. (1994). दलितों को धोखा दिया, हर–आनंद प्रकाशन, नई दिल्ली। श्याम लाल, द भंगी – ए स्वीपर कास्टः इट्स सोशियो–इकोनॉमिक पोर्ट्रेट।
8. शाह, घनश्याम. (सं.). (2002). दलित और राज्य, अवधारणा प्रकाशन कंपनी, नई दिल्ली।
9. अली, साबिर. (1994). सामाजिक–आर्थिक स्थिति की सफाई करने वालों, हर–आनंद प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ **8–15.**
10. डंकन, एम. (1982). जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकीय कम आय वाले समुदायों के लिए स्वच्छता विकल्प – एक संक्षिप्त परिचय, विश्व बैंक, वाशिंगटन।
11. डैरिल, डी. 'मोंटे. (1995). ''स्कैवेंजर्स मे बी द अर्बन साल्वेजर्स इन फ्यूचर'', द पायनियर, 31 अक्टूबर।
12. अहमद, जेड. (1980). बिहार में कम लागत वाले जल–सील शौचालय पर मूल्यांकन रिपोर्ट, समाजशास्त्र विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना।
13. गुप्ता, एस. सी. और प्रसाद, बी. जी. (1965). ''नोट ऑन लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस ऑफ स्वीपर कम्युनिटी इन लखनऊ'', ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वॉल्यूम 15, नंबर 3.
14. मलकानी, एन. आर. मैला ढोने की स्थिति जांच समिति की रिपोर्ट।
15. कालिदास, राजेंद्र., गोनेसेकरे, विमला. (2001). भेदभाव की रोकथाम और स्वदेशी लोगों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र, 13 जून।
16. डेविड, राजेंद्रन. द हटमेंट्स ऑफ द स्कैवेंजर्स एंड देयर हाउसिंग प्रॉब्लम्स, तमिलनाडु थियोलॉजिकल सेमिनरी, अरसराडी, मदुरै।
17. सुब्रमण्य, मेनन के. पी. ''द शेम ऑफ फ्री इंडियाः ए स्टडी ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक डिसएबिलिटीज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नई दिल्ली, (पैम्फेल्ट)।
18. धनपॉल, ए. (1991). तिरुनेलवेली में पलायमकोट्टई नगर पालिका के अनुसूचित जाति परिवारों के बीच गरीबी पर एक अध्ययन – कट्टाबोम्मन जिला, अप्रकाशित एम.फिल।, थीसिस, मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय, तिरुनेलवेली।
19. सिंह, मधु. (1980). सोशल ऑरिजिंस, एजुकेशनल अटेन्मेंट्स एंड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी अमंग शेड्यूल्ड कास्ट्स इन डेल्ही, अप्रकाशित थीसिस, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली।